विचार बिन्दु

जीवन का एक क्षण करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने पर भी नहीं मिलता। –चाणक्य

राजस्थान में रोजगार की राह हुई आसान

राजस्थान जैसे विशाल राज्य में रोजगार केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह युवाओं के भविष्य, परिवारों की गरिमा, गाँवों के विकास और राज्य की सामाजिक स्थिरता से जुड़ा हुआ विषय है। बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा का विस्तार और युवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं के बीच रोजगार के अवसरों का होना अत्यंत आवश्यक हो गया है। लंबे समय से राजस्थान के युवाओं के सामने यह समस्या रही है कि शिक्षा पूरी करने के बाद भी उन्हें उपयुक्त नौकरी, प्रशिक्षण या स्वरोजगार के अवसर नहीं मिल पाते थे। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के युवा, महिलाएँ, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग रोजगार की जानकारी तक पहुँचने में कठिनाई महसूस करते थे। इसी परिस्थिति में राज्य सरकार ने कई योजनाओं, नीतियों और संस्थागत प्रयासों के माध्यम से रोजगार की राह को आसान बनाने का प्रयास किया है। राजस्थान की रोजगार नीति-2026 का लक्ष्य मार्च 2029 तक लगभग 15 लाख रोजगार अवसर सृजित करना है, जिसमें वेतनभोगी नौकरियाँ, स्वरोजगार और उद्यमिता तीनों को सम्मिलित किया गया है।

राजस्थान में रोजगार की समस्या केवल नौकरियों की कमी की समस्या नहीं है। इसके पीछे कौशल और उद्योग की माँग के बीच का अंतर, ग्रामीण क्षेत्रों में निजी निवेश की कमी, रोजगार की जानकारी तक सीमित पहुँच, प्रवास की बाध्यता और महिलाओं की कम सहभागिता जैसी समस्याएँ भी हैं। बड़े शहरों के युवा जहाँ कुछ हद तक निजी क्षेत्र, आईटी, सेवा क्षेत्र और व्यापार से जुड़ पाते हैं, वहीं गाँवों के युवाओं के लिए विकल्प अक्सर सीमित रहते हैं। कई युवा शिक्षा के बाद भी ऐसे कौशल से वंचित रह जाते हैं जो उन्हें रोजगार दिला सकें। इसीलिए राज्य सरकार ने रोजगार को केवल सरकारी भर्ती से नहीं जोड़ा, बल्कि उसे कौशल विकास, इंटर्नशिप, उद्यमिता, डिजिटल प्लेटफॉर्म और निजी क्षेत्र की भर्ती से जोड़ने की दिशा में कदम उठाए हैं।

इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहल मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, जिसे आम भाषा में बेरोजगारी भत्ता योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को केवल आर्थिक सहायता नहीं देती, बल्कि उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने का प्रयास भी करती है। इस योजना के तहत पात्र पुरुष आवेदकों को प्रतिमाह 4,000 रुपये तथा महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और दिव्यांग आवेदकों को प्रतिमाह 4,500 रुपये का भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता अधिकतम दो वर्ष तक या रोजगार मिलने तक दिया जा सकता है। इस योजना की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें भत्ता पाने वाले युवाओं को केवल घर बैठे धनराशि प्राप्त नहीं होती। उन्हें सरकारी विभागों में प्रतिदिन निर्धारित समय की इंटर्नशिप करनी होती है। इससे वे कार्यालयीन कार्यप्रणाली, संचार कौशल, दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रिया और व्यावहारिक कार्य अनुभव प्राप्त करते हैं। यह अनुभव भविष्य में निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति के लिए उनकी तैयारी को मजबूत बनाता है। योजना का मूल उद्देश्य युवाओं को आर्थिक सहारा देने के साथ-साथ उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना, निर्धारित आयु सीमा में होना, वास्तव में बेरोजगार होना और परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होना आवश्यक है। रिपोर्टों के अनुसार सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदकों के लिए आयु सीमा 30 वर्ष तथा महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग आवेदकों के लिए 35 वर्ष तक रखी गई है। इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि सरकार ने उन वर्गों को प्राथमिकता दी है जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अधिक संवेदनशील माने जाते हैं।

इस योजना की उपलब्धि भी उल्लेखनीय है। रिपोर्टों के अनुसार इसके माध्यम से चार लाख से अधिक युवाओं को 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। यह राशि केवल आँकड़ा नहीं है; यह उन हजारों परिवारों की आर्थिक राहत का प्रतीक है जिनके युवा नौकरी की तलाश में आर्थिक तंगी झेल रहे थे। भत्ते से युवा कम से कम अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रख सकते हैं और रोजगार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण ले सकते हैं।

राजस्थान सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में एक व्यापक नीतिगत दृष्टिकोण भी अपनाया है। राजस्थान रोजगार नीति-2026 केवल घोषणाओं का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह राज्य के युवाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास है। इस नीति में सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में नियुक्ति, स्वरोजगार, स्टार्टअप, उद्यमिता और कौशल आधारित रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। इसका लक्ष्य मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार अवसर सृजित करना है। यह लक्ष्य बड़ा अवश्य है, परंतु इसकी दिशा सही है, क्योंकि इसमें रोजगार को एक व्यापक अवधारणा के रूप में देखा गया है।

रोजगार नीति की एक महत्वपूर्ण पहल एकीकृत डिजिटल मंच की योजना है। इसके तहत राजस्थान रोजगार पोर्टल, रोजगार कार्यालय और ई-जॉब फेयर को आपस में जोड़ा जाएगा। इससे युवा घर बैठे रोजगार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकेंगे और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के अवसरों से भी जुड़ सकेंगे। डिजिटल प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी, क्योंकि आवेदन, पात्रता, भुगतान और इंटर्नशिप से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और युवाओं को सीधे सरकारी व्यवस्था से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

रोजगार नीति में रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को 10,000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। यह राशि छोटी अवश्य है, परंतु इसका संदेश बड़ा है। यह युवाओं को यह बताती है कि निजी क्षेत्र भी सम्मानजनक रोजगार का माध्यम है और सरकार उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहित करना चाहती है। साथ ही, नौकरी शुरू करने के प्रारंभिक दिनों में आने वाली आर्थिक कठिनाई को कम करने में यह राशि सहायक सिद्ध हो सकती है।

रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केवल डिग्री या डिप्लोमा पर्याप्त नहीं होते। आज के प्रतिस्पर्धी युग में व्यावहारिक कौशल, तकनीकी ज्ञान और उद्योग की माँग के अनुसार प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया है। राजस्थान सरकार ने इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास पर विशेष जोर दिया है। युवाओं को सिलाई, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एंट्री, हेल्थकेयर और अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कौशल युवाओं को नौकरी के लिए ही नहीं, बल्कि अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए भी सक्षम बनाते हैं।

रोजगार नीति की एक महत्वपूर्ण पहल एकीकृत डिजिटल मंच की योजना है। इसके तहत राजस्थान रोजगार पोर्टल, रोजगार कार्यालय और ई-जॉब फेयर को आपस में जोड़ा जाएगा। इससे युवा घर बैठे रोजगार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकेंगे और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के अवसरों से भी जुड़ सकेंगे।

विद्यालय स्तर पर भी व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान परिषद शिक्षा द्वारा जिलावार उद्योगों की मैपिंग की जा रही है, ताकि कक्षा 9 से 12 तक के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को औद्योगिक भ्रमण, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के अवसर दिए जा सकें। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक उन्हें अक्सर सिलाई या सैलून जैसे सीमित कार्यों तक ही सीमित रखा जाता था, जबकि इस पहल से उन्हें स्थानीय उद्योगों, तकनीकी प्रशिक्षण और नए रोजगार क्षेत्रों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

राजस्थान में रोजगार मेलों को युवाओं और नियोक्ताओं के बीच सीधा सेतु बनाया गया है। राज्य सरकार ने सभी सात प्रशासनिक मंडलों जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर-में मेगा रोजगार मेले आयोजित करने की घोषणा की है। इन मेलों के माध्यम से 50,000 से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इन मेलों का महत्व इसलिए भी है कि इनमें केवल नौकरी के फॉर्म भरवाए नहीं जाते, बल्कि उद्यमिता परामर्श, मुद्रा ऋण सुविधा, अप्रेंटिसशिप और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी भी दी जाती है। इससे युवा एक ही स्थान पर नौकरी, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के विकल्प जान सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार की गारंटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शहरों में निजी नौकरियों की उपलब्धता। राजस्थान की अधिकांश आबादी गाँवों में रहती है और कृषि पर निर्भर परिवारों को पूरे वर्ष पर्याप्त कार्य नहीं मिल पाता। इसीलिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं का महत्व बढ़ जाता है। केंद्र सरकार की ग्रामीण रोजगार योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को मांग पर रोजगार देने का प्रावधान है, जबकि राजस्थान की राज्य स्तरीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित दिनों का रोजगार उपलब्ध कराती है।

इन योजनाओं से ग्रामीण श्रमिकों को सड़क निर्माण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, तालाब निर्माण, मिट्टी का कार्य और अन्य सार्वजनिक कार्यों में रोजगार मिलता है। इससे न केवल उनकी आय बढ़ती है, बल्कि गाँवों की बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ भी सुधरती हैं। जब गाँव में सड़कें, तालाब, जल स्रोत और सार्वजनिक संपत्तियाँ बेहतर होती हैं, तो वहाँ के लोगों को प्रवास करने की बाध्यता भी कम होती है। इस प्रकार ग्रामीण रोजगार योजनाएँ आजीविका और ग्रामीण विकास, दोनों को साथ-साथ आगे बढ़ाती हैं।

राजस्थान सरकार ने महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और दिव्यांगजनों के लिए भी रोजगार योजनाओं में विशेष प्रावधान रखे हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में इन वर्गों को पुरुषों की तुलना में 500 रुपये अधिक मासिक भत्ता दिया जाता है। यह अंतर केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समानता की दिशा में एक व्यावहारिक कदम है। महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ना राज्य के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।

महिलाओं के लिए घरेलू उद्यम, सिलाई-बुनाई, डेयरी, मोरिंगा खेती, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल सेवाओं से जुड़े अवसर भी बढ़ाए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को ऋण, प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ने के अवसर दिए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण महिलाएँ आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बन रही हैं और परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी भी बढ़ रही है। जब महिलाएँ आय अर्जित करती हैं, तो उनका सम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति भी सुधरती है।

रोजगार के लिए हर युवा को सरकारी या निजी नौकरी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है। युवाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श, ऋण सुविधा और बाजार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुद्रा ऋण जैसी योजनाओं के माध्यम से युवा साइकिल रिपेयरिंग, मोबाइल शॉप, किराना दुकान, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, पोल्ट्री, नर्सरी, कपड़ा व्यवसाय, कैटरिंग और डिजिटल सेवाओं जैसे कार्य शुरू कर सकते हैं। रोजगार मेलों में भी उद्यमिता परामर्श और ऋण सुविधा के लिए विशेष स्टॉल लगाए जाते हैं, जिससे युवाओं को व्यवसाय शुरू करने का मार्ग आसान होता है।

राजस्थान रोजगार पोर्टल ने युवाओं के लिए रोजगार खोजने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। इस पोर्टल पर युवा अपना पंजीकरण कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता और कौशल की जानकारी दे सकते हैं, रोजगार मेलों की सूचना प्राप्त कर सकते हैं और नियोक्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। इससे युवाओं को रोजगार की तलाश में शहर-शहर भटकना नहीं पड़ता। वे अपने गाँव या शहर से ही रोजगार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल माध्यम से पारदर्शिता बढ़ने से योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुँचने की संभावना भी बढ़ती है।

फिर भी, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि राजस्थान में रोजगार के क्षेत्र में जितनी प्रगति हुई है, उतनी ही चुनौतियाँ भी शेष हैं। प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति की गारंटी, ग्रामीण क्षेत्रों में निजी निवेश की कमी, उद्योगों का सीमित विस्तार, महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा और युवाओं को आधुनिक कौशल से जोड़ना अभी भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कई बार प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवा को उपयुक्त नौकरी नहीं मिल पाती, जिससे उनका उत्साह कम हो जाता है। इसलिए केवल प्रशिक्षण केंद्र खोलना पर्याप्त नहीं है; प्रशिक्षण के बाद नियोक्ताओं से संपर्क, प्लेसमेंट और कार्यस्थल पर निगरानी भी आवश्यक है।

आगे की राह के लिए राज्य सरकार को औद्योगिक निवेश, स्टार्टअप संस्कृति, कृषि प्रसंस्करण, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, खनन और आईटी क्षेत्र में अधिक निवेश करना होगा। राजस्थान में सौर ऊर्जा, पर्यटन, हस्तशिल्प, खनिज, कृषि और पशुपालन की अपार संभावनाएँ हैं। यदि इन क्षेत्रों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित मानव संसाधन और बाजार से जोड़ा जाए, तो लाखों युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। साथ ही स्कूल और कॉलेज स्तर पर करियर परामर्श को मजबूत करना, इंटर्नशिप की गुणवत्ता सुधारना और रोजगार मेलों में वास्तविक नियुक्तियाँ सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

राजस्थान में रोजगार की राह वास्तव में पहले की तुलना में आसान हुई है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ने बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा दिया है, जबकि रोजगार नीति-2026, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार मेले, डिजिटल पोर्टल और उद्यमिता सहायता ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि ये योजनाएँ केवल कागजी घोषणाएँ न रहें, बल्कि धरातल पर पारदर्शी और प्रभावी रूप से लागू हों। यदि युवाओं को समय पर भत्ता, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, वास्तविक इंटर्नशिप और सम्मानजनक नियुक्ति के अवसर मिलते रहें, तो राजस्थान के युवा केवल नौकरी माँगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाले उद्यमी भी बन सकेंगे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, प्रवास कम होगा और युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। राजस्थान के लिए यही सच्चा रोजगार क्रांति का मार्ग है।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

सामाजिक समरसता : एक नेक विचार अथवा वर्तमान में मात्र राजनीतिक शोशेबाजी



महावीर सिंह

आपने कुछ राजनीतिक दलों और कुछ सांस्कृतिक संगठनों द्वारा सामाजिक समरसता शब्द का बहुधा उपयोग करते सुना होगा। आइए, इन शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें।

इसका अर्थ समझने के लिए सर्वप्रथम इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा कि भारतीय समाज विभिन्न वर्गों, धर्मों और जातियों में बंटा हुआ है। तो फिर सामाजिक स्तर पर इन विभिन्न जातियों, धर्मों आदि के लोगों में दैनिक एकल व सामूहिक रूप से सौहार्दपूर्ण व्यवहार के आधार क्या हों? यह समझाने के लिए ही सामाजिक समरसता जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है।

समरसता का शाब्दिक अर्थ है- 'समान भाव' या 'सबके साथ एक जैसा तालमेल और सामंजस्य रखना'। विभिन्न प्रकार के लोग, विचार, परिस्थितियाँ होने पर भी उनमें कड़वाहट न हो, बल्कि अपनापन बना रहे। इसे सामाजिक स्तर पर विस्तार दें तो सामान्य समझ कहती है यह तभी संभव है जब जाति, वर्ग, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी इंसानों को बराबर समझा जाए अर्थात विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों के बीच समन्वय, एकता और संतुलन स्थापित करना। इसकी प्राथमिक शर्त है कि हर व्यक्ति को विकास करने का न्यायपूर्ण तरीके से उचित अवसर मिले। बिना इसके, भारत जैसे अनेक प्रकार की विविधताओ वाले देश में,जहां, अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं के लोग रह ते है सामाजिक समरसता संभव नहीं होगी।

भारत की नई शिक्षा नीति के अनुसार, सामाजिक समरसता के लिए समाज में लोगों के बीच उनके मूल स्थान, नस्लीय मूल, वैवाहिक स्थिति, जातीयता, रंग, लिंग, जाति, आयु, व्यवसाय, राष्ट्रीयता को महत्व न देकर परस्पर प्रेम, विश्वास, प्रशंसा, शांति, सद्भाव, सम्मान और उदारता को महत्व दिया जाना चाहिए।न्यायपूर्ण तरीके से उचित अवसर मिले बिना ऊपर लिखे सद विचारों की प्राप्ति संभव कैसे होगी?

वर्ण/जाति व्यवस्था के संबंध में रूढ़िवादी विचार यह है कि यह दैवीय व्यवस्था है। समाज इस प्रकार गठित हो कि वह सुचारू रूप से चले। इसके लिए भगवान ने स्वयं अपने शरीर के विभिन्न अंगों से मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षित्रय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र बनाए।

दैवीय व्यवस्था के संबंध में गांधीजी के विचार को ध्यान में रखना चाहिए। गांधी जी का स्पष्ट मत था - "हिंदू धर्मशास्त्रों में मेरे विश्वास का यह अर्थ नहीं कि मैं उनके एक-एक शब्द को दैवीय प्रेरणा से उद्भूत मानता हूं। मैं किसी भी व्याख्या को मानने से इनकार करता हूं जो तर्क व नैतिक दृष्टि के प्रतिकूल हो।"

वस्तुत: यह दैवीय व्यवस्था की कल्पना, बुद्धिमान व चालाक व्यक्तियों द्वारा मनुष्यों, परिवारों व समाज पर नियंत्रण की कला थी जिसे धार्मिक व ईश्वरीय चोला पहनाकर स्थायी किया गया। अब, संविधान के आगे इस दैवीय व्यवस्था का कोई महत्व नहीं है। किंतु वर्तमान में भी इस व्यवस्था की श्रेष्ठता बताने के लिए इक्के दुक्के अपने आप को सबसे उच्च वर्ग के मानने वाले कतिपय धार्मिक नेता, राजनेता और बौद्धिक वर्ग के लोग बयानबाजी करते रहते है।

जब चालक लोगों ने यह तथाकथित दैवीय व्यवस्था बनाई तब, मुख्यत कृषि और पशुपालन पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी।शहरों का भी ज्यादा विस्तार नहीं था। जनसंख्या के लिहाज से कामों की कमी नहीं थी।ऐसी सामाजिक संरचना और अर्थ व्यवस्थाओं में रोजी रोटी के लिए वर्ग संघर्ष की संभावना अत्यंत न्यून थी।उस समय के प्रचलित काम थे किसानी, व्यापार, लकड़ी व चमड़े के कारीगर, कुम्हारी व चुनाई का कार्य, नाई का कार्य, साहूकारी,सुनारी लुहारी, सेना, राज की नौकरी, शिक्षक, वैद्यिगरि आदि पुश्तैनी कार्य आदि थे। समाज को आवश्यकतानुसार विभिन्न सेवाएं मिल जाती थी और काम के जानकारों को काम मिल जाता था। रोजगार को लेकर लोगों में असंतोष नहीं था।आज बेराजगारी की जो समस्या है वैसी शायद उस समय नहीं थी।

प्रारंभ में पेशा बदलने में जाती बाधक नहीं रही होगी किंतु कालांतर में पेशे जाती आधारित बना दिए और उनको छोड़ना आसानी से संभव नहीं था अर्थात चर्मकार का बेटा चर्मकारी का ही काम करेगा, मेहतर का बेटा ही मेहतरी का काम करेगा और यह लोग वेदपाठी व शिक्षक नहीं बन सकतें। जाती और पेशे को एक साथ बांध दिया, जातिगत पेशा छोड़कर अपनी इच्छा का पेशा अपनाना कठिन था।जातिगत पेशा छोड़ने वालों के लिए दंड भी था--- सबसे बड़ा दंड समाज से बहिष्कृत करना।

शास्त्रों में उल्लेखित ब्राह्मणों से (आज की ब्राह्मण जाति नहीं, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्णित ब्राह्मण) अपेक्षा की गई थी कि वे सादा-सरल-वैरागी जैसा जीवन जिएंगे और समाज का नेतृत्व करेंगे। आज धरातल पर ऐसी स्थितियां हैं ही नहीं। आज जिसे हम ब्राह्मण के रूप में जानते हैं, वह तो वैश्य, क्षत्रिय, शूद्रों वाले सारे कार्य करता है। कोई भी गरीब किंतु शिक्षित, बेरोजगार व्यक्ति शास्त्रीय व्याख्यानुसार ब्राह्मण होने के सारे मापदंड पूरे करता है।

कुछ विचारकों का मानना है कि सामाजिक समरसता ही सामाजिक समानता है जिसमें जाति आधारित भेदभाव नहीं होगा, अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं होगा और समाज के सभी वर्गों के बीच प्रेम, सद्भाव और एकता होगी। कुछ अन्य विचारक इस बात को महत्व देते हैं कि वास्तविक सामाजिक समरसता में मनुष्य दूसरे मनुष्य को एक ही ईश्वर की संतान समझता है, सबमें एक ही चैतन्य है और इस बात को हृदय से स्वीकार करता है, न कि दिखावटी प्रेम।

गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा - "मानस की जात सबै एकै पहचानबो" अर्थात सभी मनुष्यों को एक ही जाति का मानना चाहिए। कबीर जी कहते हैं- "लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।" सार यही है कि चारों ओर ईश्वरीय ऊर्जा ही है, सब समान हैं।

प्रसिद्ध इतिहासकारों के अनुसार सामाजिक समरसता के चार प्रमुख घटक हैं: (1) संविधान जिसमें धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध हो (2) सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन (3) ऐसी शिक्षा जिससे मानवीयता, सद्भाव, भ्रातृत्व और समतामूलक गुणों का विकास हो (4) मीडिया का उद्देश्य निष्पक्ष, सटीक और सभ्य भाषा में जनसेवा करना हो।

डॉ. भीमराव अंबेडकर, जिनके जन्मदिन को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया गया है, के अनुसार बिना सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सामाजिक समरसता एक प्रतीकात्मक विचार मात्र है। प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता के अनुसार बराबर अवसरों की उपलब्धता ही सच्ची सामाजिक समरसता की नींव है।

सामाजिक समरसता पर पिछले 200 साल के विश्व के सबसे विश्वसनीय नेता महात्मा गांधी के विचार जाने बिना इस विषय के साथ न्याय नहीं होगा। गांधी जी जाति व्यवस्था और श्रम में भेद के विरोधी थे। वे उन सभी प्रथाओं के विरोधी थे जो शोषण और हिंसा पर आधारित हों। 1931 में उन्होंने लिखा था कि अंतर्जातीय विवाहों व भोज पर प्रतिबंध अनावश्यक है। विभिन्न वर्गों के लोग परस्पर विवाह कर सकते हैं, साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। (स्त्रोत: महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा के साहित्य से - डॉ. शंभू जोशी)

धरातलीय स्थिति क्या है?

कोई भी सरकार रही हो, सभी ने यह प्रयास किया कि जिन वर्गों के साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जाए। इसके लिए विशेष योजनाएं बनीं, संसद-विधानसभाओं-पंचायतों में स्थान आरक्षित किए गए, सरकारी नियुक्तियों व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया। एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, अल्पसंख्यकों आदि के लिए आयोग बनाए गए। किंतु सामाजिक समरसता के लिए बनाए गए संवैधानिक घटक को भी कमजोर करने के प्रयास भी हो रहे हैं। उदाहरणार्थ सरकारी नियमित पदों के बदले संविदा कर्मचारी रख लेना, सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपना और शीर्ष पदों के समीप वाले पदों पर लेटरल नियुक्तियां करना।

आज सरकार के पास इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों की कमी नहीं, तो फिर सरकार में शीर्ष के 2,4 पदों के जिनमें किसी विशेष क्षेत्र के विशिष्ट प्रकार के अनुभव की आवश्यकता हो,उनके अतिरिक्त, नीचे के पदों पर बिना आरक्षण लेटरल नियुक्तियों के प्रयास का औचित्य समझ में नहीं आता।

सार्वजनिक स्थानों जैसे दफ्तर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चाय की दुकानों पर सामान्यत: सेवा लेने-देने वालों की कोई जाति नहीं पूछता। किंतु आज भी वंचितों की बरातों पर पथराव, दूल्हे को घोड़ी पर न चढ़ने देना, सिर मुंडवा देना, महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार जैसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। उच्च वर्ण के व्यक्तियों ने भगवान की कथा सुनाने पर भी एकाधिकार बना रखा है, अन्यथा उत्तरप्रदेश में चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति द्वारा भागवत कथा सुनाने पर सिर मुंडवाना, नाक रगड़वाना जैसा व्यवहार नहीं होता।

कहा जाता है, 140 करोड़ का देश है, छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं। फिर ऐसी घटनाएं तथाकथित उच्चवर्णीय व्यक्तियों के साथ प्राय: क्यों नहीं सुनने को मिलतीं? बहुत से राजनीति से जुड़े लोग फोटो खिंचवाकर प्रचार के लिए वंचितों के घरों पर प्रायोजित भोजन करते हैं, यह महज दिखावा है।

यह भी कोई छुपी हुई बात नहीं कि अब भी कुछ पदों, सेवाओं के लिए अलिखित आरक्षण है ही। कुछ संस्थाओं में तो भारत के 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व तो 2,4,5,10 प्रतिशत से अधिक नहीं। कुछ संस्थाओं में तो चयन विशिष्ट परिवारों, समूहों, संगठनों तक सीमित होता जा रहा है। यह सामाजिक समरसता के अनुकूल है या प्रतिकूल इसका निर्णय मैं पाठकों पर छोड़ता हूं।

और अंत में....

दिल पर हाथ रखकर सोचें, क्या आपने पिछले 40-50 साल में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, पाखंड आधारित पूजा, तर्कहीन प्रवचनों और भगवान के नाम पर चंदे की बोली लगवाने जैसे कार्यों के विरुद्ध कोई सशक्त जनांदोलन देखा?

और मीडिया, जो सामाजिक समरसता का महत्वपूर्ण घटक है, क्या वह अपना दायित्व निभा रहा है?

-महावीर सिंह पूर्व आईएएस

दीपावली की मिठास में मिलावट का ज़हर!

त्योहार की खरीदारी में सतर्क रहें, सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो



डॉ. लीलाधर दोचानिया

दीपावली खुशियों, उल्लास, रोशनी और आपसी प्रेम का त्योहार है। इस अवसर पर घरों में मिठाइयों की खुशबू महकती है, रिश्तेदारों और मित्रों को उपहार दिए जाते हैं तथा बाजारों में खरीदारी की रौनक देखते ही बनती है। लेकिन त्योहार की इसी रौनक के बीच एक गंभीर चिंता भी सिर उठा रही है। कहीं मिठास के नाम पर लोगों की थाली में मिलावट और बीमारियों का जहर तो नहीं परोसा जा रहा?

त्योहारों के दौरान मिठाइयों, मावे, पनीर, घी, दूध, तेल, नमकीन और सूखे मेवों की मांग अचानक बढ़ जाती है। अधिक मुनाफा कमाने की लालच में कुछ असामाजिक कारोबारी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता करते हैं। मिलावटी मावा, नकली पनीर, घटिया घी, मिलावटी खाद्य तेल और निर्धारित मानकों के विरुद्ध रंगों का इस्तेमाल आम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने भी दीपावली के मद्देनजर राज्यों को विशेष निगरानी, निरीक्षण और खाद्य नमूनों की जांच के निर्देश दिए हैं। दूध एवं दुग्ध उत्पादों, मिठाइयों, नमकीन, खाद्य तेल और घी पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

राजस्थान में भी शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई तेज की गई है। जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के नमूने लेने और संदिग्ध सामग्री जब्त करने की कार्रवाई सामने आई है।

मिलावट से बचने के लिए उपभोक्ता क्या करें?

सबसे पहले मिठाइयां और अन्य खाद्य सामग्री विश्वसनीय एवं प्रतिष्ठित दुकानों से ही खरीदें। पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि, अंतिम उपयोग तिथि, सामग्री का विवरण और लाइसेंस नंबर अवश्य देखें। खरीदारी का बिल लेना न भूलें।

खुली मिठाइयों की गुणवत्ता, उनकी स्वच्छता और रखरखाव पर विशेष ध्यान दें। असामान्य रंग, गंध, स्वाद अथवा खराब स्थिति में रखे खाद्य पदार्थ खरीदने से बचें। पनीर, मावा और घी खरीदते समय भी विश्वसनीय विक्रेता को प्राथमिकता दें। केवल बाहरी रंग, चमक या स्वाद के आधार पर किसी खाद्य पदार्थ को शुद्ध मान लेना उचित नहीं है। घरेलू जांच के कुछ तरीके प्रारंभिक संकेत दे सकते हैं, लेकिन खाद्य पदार्थ की शुद्धता की अंतिम पुष्टि प्रयोगशाला जांच से ही होती है।

प्रशासन की जिम्मेदारी भी कम नहीं

त्योहार के समय खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। केवल औपचारिक निरीक्षण पर्याप्त नहीं हैं। मिठाई बनाने वाली फैक्ट्रियों, गोदामों, थोक विक्रेताओं और खुदरा दुकानों पर नियमित जांच होनी चाहिए। संदिग्ध खाद्य सामग्री के नमूने लेकर शीघ्र प्रयोगशाला जांच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रमुख बाजारों में जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। जहां सुविधा उपलब्ध हो